राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापुर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, गुरुवार, 08 जनवरी 2026
वर्ष 14, अंक 265, पृष्ट 04, मूल्य: 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

गोपाल बाग में भाकियू का धरना, सिंचाई संकट और गन्ना उतरवाई में अवैध वसूली पर उबाल ..03

संदिग्ध हालात में 12वीं के छात्र की मौत, 4 लोगों पर हत्या का आरोप..04

जलवायु कार्यकर्ता द्वारा संचालित एनजीओ पर विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोप में ईडी की छापेमारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को जलवायु कार्यकर्ता हरजीत सिंह और उनकी पत्नी ज्योति अवस्थी द्वारा संचालित एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से जुड़े ठिकानों पर कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन (फेमा) के मामले में तलाशी अभियान चलाया. मामले के जानकार लोगों के हवाले से बताया कि ईडी हरजीत सिंह के संगठन - सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल) - को प्राप्त 6 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी निधि की जांच कर रहा है. आरोप है कि इन पैसों का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नैरेटिव गढ़ने में किया गया. हरजीत सिंह बहुपक्षीय जलवायु मंचों पर ग्लोबल साउथ के अधिकारों के पैरोकार के रूप में एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. फेमा के तहत कथित उल्लंघनों को लेकर सिंह के आवास तथा दिल्ली और गाजियाबाद स्थित एनजीओ के कार्यालयों पर छापेमारी की गई. हालांकि, एजेंसी ने यह नहीं बताया कि छापों में फेमा उल्लंघन से संबंधित क्या साक्ष्य मिले।

एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'एसएसपीएल और उसके संस्थापकों को 2021 से 2025 के बीच

पर्याप्त मात्रा में विदेशी धनराशि प्राप्त हुई है. ये रेमिटेंस कंसल्टेंसी चार्ज के नाम पर मिले थे. हालांकि, विदेश में रेमिटेंस भेजने वालों द्वारा की गई फाइलिंग के क्रॉस-वेरिफिकेशन से पता चला है कि ये हस्तांतरण वास्तव में भारत में फॉसिल फ्यूल नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी (एफएफ-एनपीटी) के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए नैरेटिव चलाने के लिए किए जा रहे थे, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं.' फॉसिल फ्यूल नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी एक प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों की आपूर्ति को सीधे निशाना बनाकर जलवायु संकट पर काबू पाना है. हालांकि यह बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह नए जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं की मंजूरी समाप्त करने, मौजूदा उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से कम करने और देशों को स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में वित्तीय व तकनीकी सहायता देने पर जोर देता है।

यह मुख्यतः एक वैश्विक नागरिक समाज अभियान है, जिसे सैकड़ों शहरों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और नोबेल पुरस्कार विजेताओं सहित कई संस्थाओं का समर्थन प्राप्त है. अधिकारी ने यह भी दावा किया कि एसएसपीएल की गतिविधियां - जैसे खेती में ऑर्गेनिक तरीकों को बढ़ावा देना और किसानों को ऑर्गेनिक फल और सब्जियां बेचने में मदद करना सिर्फ़ दिखावे की गतिविधियां हैं - और इस कंपनी का असली मकसद विदेशी प्रभावशाली समूहों की ओर से भारत में एफएफ-एनपीटी को बढ़ावा देना है. अखबार के अनुसार, नाम न छापने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि सिंह के आवास से लगभग 45 शराब की बोतलें मिलीं, जो आबकारी नियमों का उल्लंघन है. गाजियाबाद के सहायक आबकारी आयुक्त संजय सिंह ने कहा, 'ईडी से मिली सूचना के आधार पर हमने हरजीत सिंह के आवास पर एक टीम भेजी है. आबकारी नियमों के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी.' एक दूसरे ईडी अधिकारी ने कहा कि इस एनजीओ को मुख्य रूप से क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क (सीएएन), ऑयस्टर एचआर और स्टैंड अर्थ से फंडिंग मिलती है. वैश्विक जलवायु जगत में एक जाना-पहचाना नाम रहे हरजीत सिंह पिछले दो दशकों से गैर-सरकारी स्तर पर जलवायु मुद्दों की प्रभावशाली आवाज रहे हैं. वे पर्यवेक्षक संगठनों की ओर से अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं. जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित और संवेदनशील देशों के लिए बनाए गए 'लॉस एंड डैमेज फंड' की रूपरेखा तैयार करने में भी उनके महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा होती रही है. इस फंड की स्थापना वर्ष 2023 में दुबई में हुई थी. विकसित देशों द्वारा जलवायु कार्रवाई में ढिलाई के खिलाफ ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के रूप में हरजीत सिंह के विचार अक्सर मीडिया में स्थान पाते रहे हैं. हालिया साक्षात्कारों में उन्होंने अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई को 100 मीटर मानने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी- जिस आदेश पर बाद में अदालत ने रोक लगा दी।

महाराष्ट्र में ये क्या हुआ? अंबरनाथ में भाजपा-कांग्रेस ने मिलाया हाथ, एकनाथ शिंदे हक्का-बक्का

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महाराष्ट्र की सियासत में नया खेल देखने को मिला है. कांग्रेस-मुक्त भारत का नारा लगाने वाली भाजपा ने ठाणे के अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस से हाथ मिला लिया है. भाजपा ने शिवसेना के शिंदे गुट को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस के साथ सत्ता का रास्ता चुना है. अंबरनाथ में भाजपा-कांग्रेस गठबंधन से राजनीति गरमा गई है. इस भाजपा और कांग्रेस गठबंधन में अजित पवार की एनसीपी भी शामिल है. इस तरह अंबरनाथ नगरपालिका में सत्ता का संतुलन बदल गया है और अब शिवसेना को विपक्ष की बेंच पर बैठना पड़ेगा।

दरअसल, अंबरनाथ नगर परिषद में हुए राजनीतिक घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है. शिंदे गुट को सत्ता से दूर रखने के लिए भाजपा ने अंबरनाथ में सीधे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सत्ता का रास्ता चुना है. शिंदे गुट को दरकिनार करते हुए अंबरनाथ नगर परिषद में भाजपा-कांग्रेस का एक अप्रत्याशित गठबंधन साकार हुआ है. इस गठबंधन की बदौलत भाजपा बहुमत की ओर बढ़ रही है. इस गठबंधन की वजह से ही भाजपा की तेजश्री करंजुले ने अंबरनाथ नगर परिषद में महापौर का पद जीत लिया है।

भाजपा को स्पष्ट बहुमत

कुल 32 पार्षदों के गठबंधन से भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा. इसमें भाजपा के 14, कांग्रेस के 12 और एनसीपी (अजीत पवार समूह) के 4 पार्षद शामिल हैं. इस गठबंधन को 'अम्बरनाथ विकास अघाड़ी'

नाम दिया गया है. हालांकि, इन घटनाक्रमों से शिवसेना शिंदे समूह में भारी असंतोष है. शिवसेना शिंदे समूह ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए इस गठबंधन को 'अभद्र युति (गठबंधन)' बताया है।

शिंदे गुट के विधायक नाराज

शिंदे समूह के विधायक डॉ. बालाजी किनिकर ने कांग्रेस-मुक्त भारत की बात करने वाली भाजपा पर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके शिवसेना पर हमला करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस-मुक्त भारत की घोषणा करने वाली भाजपा ने ठाणे के अम्बरनाथ में नगर परिषद में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है. इस गठबंधन को शिवसेना ने पीठ में छुरा घोंपने जैसा है. वहीं, भाजपा ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है।

शिंदे गुट ने किया भाजपा पर पलटवार

भाजपा उपाध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटिल ने शिंदे समूह पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर वे पिछले पच्चीस वर्षो से भ्रष्टाचार में लिप्त शिंदे समूह के साथ सत्ता में होते तो यह एक बेहद ही अनुचित गठबंधन न होता. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अंबरनाथ नगर परिषद के लिए शिंदे समूह के साथ महागठबंधन पर कई बार चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन उनके नेताओं से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

इस गठबंधन से किसे टेंशन

एक ओर जहां भाजपा-कांग्रेस गठबंधन अंबरनाथ नगर परिषद में सत्ता के बंटवारे को स्पष्ट कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस गठबंधन ने महायुति और महागठबंधन में तनाव पैदा कर दिया है. अंबरनाथ में यह अनुचित गठबंधन अनुचित है या अपरिहार्य, इस पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप आने वाले समय में और भी तेज होने की संभावना है. लेकिन यह बात सच है कि एकनाथ शिंदे को यह फैसला जरूर खटका होगा।

भाजपा-कांग्रेस गठबंधन पर शिंदे के बेटे का रिएक्शन

अंबरनाथ में भाजपा-कांग्रेस गठबंधन पर एकनाथ शिंदे के बेट श्रीकांत शिंदे का रिएक्शन आया है. श्रीकांत शिंदे ने कहा, अंबरनाथ में भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन, यह सवाल पूरी तरह से हमारी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के लिए है. क्क्षक नेता इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे. कई सालों से भाजपा और शिवसेना केंद्र, राज्य और नगर निगम में गठबंधन में हैं. यह गठबंधन अटूट रहना चाहिए. अंबरनाथ में शिवसेना सत्ता में थी और शिवसेना ने अंबरनाथ में अच्छा विकास कार्य किया. अब वे जो भी फैसला लेना चाहते हैं, शिवसेना विकास की राजनीति करने वाले के साथ होगी।

संक्षिप्त ख़बरें

मस्जिद का हिस्सा भी तोड़ दिया, इसलिए लोग भड़के..दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर एक्शन पर बोले स्थानीय मुस्लिम

दिल्ली के रामलीला मैदान के पास स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास का अतिक्रमण हटा दिया गया है. स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है. जबकि पुलिस ने हालात काबू में रखने के लिए देर रात आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं. तुर्कमान गेट के पास रह रहे लोगों का कहना है कि प्रशासन ने मस्जिद का कुछ हिस्सा ढहा दिया है.यही वजह है कि लोग विरोध कर रहे हैं. दिल्ली एमसीडी ने रात 1 बजे कार्रवाई शुरू की थी. यह कार्रवाई सुबह 7 बजे तक जारी रही. फिलहाल फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आगे की गली को बंद किया गया है. गली में रहने वाले लोगों का कहना है कि घर में दूध नहीं है,लोग काम पर नहीं निकल सकते हैं।

गली के लोगों का क्या है कहना?

तुर्कमान गेट की उसे गली में रहने वाले मुस्लिम लोगों का कहना है कि एमसीडी ने गलत कार्रवाई की है. मुस्लिम महिला का कहना है कि जितनी जगह थी सिर्फ उसे तोड़ना चाहिए था. उन्होंने मस्जिद की भी कुछ हिस्से को तोड़ा है. इसी वजह से पब्लिक गुस्से में थी. मस्जिद के ही पास रहने वाले नसीम नाम के शख्स का कहना है कि पब्लिक को डर था की मस्जिद पर एमसीडी हमला न कर दे, उसे तोड़ ना दे. इसीलिए लोग इकट्ठे हुए थे. पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने आंसू गैस की गोली चलाई और फायरिंग की।

मस्जिद की गली को किया गया बंद

देर रात फेज ए इलाही मस्जिद के आसपास अवैध रूप से किया गया अतिक्रमण को तोड़ा गया. यहां 30 से ज्यादा बुलडोजर ने की कार्रवाई की है. फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आगे की गली को बंद किया गया है. गली में रहने वाले लोगों का कहना है कि घर में दूध नहीं है,लोग काम पर नहीं निकल सकते हैं. गली में रहने वाले लोगों ने इस कार्यवाही पर बोले कि इस कार्यवाही करने से पहले सूचना दिया जाना चाहिए था. अभी गली सामने से बंद कर दी गई है.तुर्कमान गेट गली में जगह जगह लोग इकट्ठा खड़े हुए है. फिलहाल कार्रवाई आज बंद कर दी गई है. इसके बाद भी पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात है।

दिल्ली सीएम ने कहा- भगत सिंह ने कांग्रेस सरकार के ख़िलाफ़ बम फेंका था, विपक्ष बोला- इतिहास का रीमिक्स

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने मंगलवार (6 जनवरी) को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तंज कसते हुए कहा कि वे इतिहास का 'रीमिक्स' बना रही हैं. उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब इसी दिन विधानसभा में अपने भाषण के दौरान रेखा गुप्ता ने कथित तौर पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का उल्लेख करते हुए कुछ गलत तथ्य बोले. दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण के दौरान रेखा गुप्ता ने कहा कि भगत सिंह और उनके साथियों ने 'बहरी कांग्रेस सरकार' के खिलाफ बम फेंका था - जबकि वे उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे. कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से यह टिप्पणी अनजाने में निकल गई. इसके बाद आप विधायक संजीव झा ने इसे 'इतिहास का अपडेटेड संस्करण' करार दिया।

झा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, 'आज दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इतिहास का एक नया 'अपडेटेड' संस्करण पेश किया है. ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले शहीद-ए-आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंकने वाला बताया जा रहा है.'

बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने आगे कहा कि अब इतिहास 'रीमिक्स मोड' में चल रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'अगली बार शायद यह भी सुनने को मिल जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गांधीजी के निर्देश पर अपने साम्राज्य

का विस्तार किया था.' आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने 'देश को शर्मसार कर दिया.' उन्होंने कहा, 'यह बात तो स्कूली बच्चों को भी पता है कि शहीद भगत सिंह ने 1929 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था।'

रेखा गुप्ता ने क्या कहा

मंगलवार को बजट सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के इतिहास का उल्लेख किया. उन्होंने महाभारत के संदर्भ से शुरुआत की, पृथ्वीराज चौहान जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का जिक्र किया और फिर 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में किए गए बम विस्फोट की बात कही. उन्होंने कहा, 'दिल्ली ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की क्रांति को सुना है, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फेंका था.' यह बयान विधानसभा की आधिकारिक वेबकास्ट के लगभग 1 घंटे 45 मिनट के समय पर दर्ज है. आप की ओर से किए गए इन तंजों और टिप्पणियों पर न तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और न ही दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है.

आप विधायकों की 'नो एंट्री'!

इस बीच, आम आदमी पार्टी ने बुधवार (7 दिसंबर) को आरोप लगाया कि विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह को दिल्ली विधानसभा परिसर में घुसने से रोक दिया गया है. आप विधायक संजीव झा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'कल दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत नही बल्कि बहरी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बम फोड़ा था. भगत सिंह वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली की सेंट्रल असेम्बली में बम फोड़ा, और उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी.' उन्होंने आगे कहा, 'आज दिल्ली पुलिस हम चुने हुए विधायकों को सदन तक जाने से रोक रही है. ये लोग अंग्रेजों के पिट्ठू, जो लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं? हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं, शहीद भगत सिंह का अपमान करने वालों माफी मांगो!'

वहीं, आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाजपा सरकार में तानाशाही की हदें पार हो चुकी हैं. पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, ' रेखा गुप्ता सरकार के फ़र्ज़ीवाड़े के ख़िलाफ़ मजबूती से आवाज़ उठाने की वजह से भाजपा की दिल्ली पुलिस आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा के प्रांगण तक में नहीं जाने दे रही है. उन्हें सड़क पर ही रोक दिया जा रहा है.' तीनों आप विधायकों को सोमवार को स्पीकर ने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाकी तीन दिनों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के भाषण में बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया था।

अंकिता भंडारी केसः दुष्यंत गौतम से जुड़े पोस्ट हटाएं... कांग्रेस- AAP को दिल्ली H C का आदेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने दोनों पार्टियों से कहा है कि वे बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम से जुड़े उन पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटाएं, जिनमें उन्हें 2022 के अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा गया है. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने यह आदेश दुष्यंत कुमार गौतम द्वारा दायर मानहानि के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया. कोर्ट ने राजनीतिक दलों को भविष्य में भी ऐसी कोई सामग्री पोस्ट करने से मना किया है, जिसमें दुष्यंत गौतम को इस हत्या मामले का 'VIP' बताया गया हो. जज ने साफ किया कि अगर पार्टियां खुद इन पोस्ट को नहीं हटातीं, तो सोशल मीडिया कंपनियां खुद इन्हें हटा देंगी. अदालत ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहित अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ भी आदेश पारित किया।

दुष्यंत गौतम से जुड़े पोस्ट तुरंत हटाएं

कोर्ट का मानना है कि बिना सबूत के बीजेपी नेता को हत्या के मामले से जोड़ना गलत है, इसलिए उनसे जुड़ी ऐसी सभी पोस्ट तुरंत हटाई जाएं. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर अपलोड की गई इससे जुड़ी सारी पोस्ट और वीडियो को हटा दें. इस मामले में अगली सुनवाई चार मई को होगी।

अंकिता भंडारी की हत्या 2022 में हुई थी

अंकिता भंडारी की 2022 में हत्या कर दी गई थी. वह पौड़ी जिले के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं. बाद में रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो कर्मचारियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को में गिरफ्तार किया गया और सेशन कोर्ट ने उन्हें इस अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई. हाल ही में अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था, जिसमें एक कथित 'वीआईपी' का जिक्र किया गया है, जिसका इस मामले से कथित तौर पर संबंध बताया जाता है. सनावर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी होने का दावा करती हैं. अपने मुकदमे में गौतम ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ-साथ सनावर, राठौर, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उसके अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट आलोक शर्मा से दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है. पिछले कुछ दिनों से इस केस को लेकर काफी प्रदर्शन हो रहा है।

यूपी कैबिनेट विस्तार का पहला चहरा तय! योगी सरकार में सपा की बागी विधायक पूजा पाल बनेंगी मंत्री?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ- उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कुछ दिनों से कवायद काफी तेज हो गई है। पिछले दिनों सीएम योगी की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही सुगबुगाहट को और अधिक मजबूती मिली है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। ये नाम सपा की बागी विधायक पूजा पाल का है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूजा पाल को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है।

सीएम योगी की तारीफ पर सपा ने पार्टी से निकाला

यूपी के कौशांबी जिले की चायल विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर विधायक पूजा पाल को सीएम योगी की तारीफ

करने की वजह से पार्टी से निकाला गया है। उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ गैंग के खिलाफ योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि इस सरकार में उन्हें इंसाफ मिला। इतना ही नहीं पूजा पाल ने अतीक अहमद के साम्राज्य के अंत का जिक्र विधानसभा में भी करते हुए सीएम योगी को धनयवाद बोला था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात भी की थी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। बता दें कि अतीक अहमद ने पूजा पाल के पति और बसपा विधायक राजू पाल की हत्या करवाई थी।

चुनाव में BJP का प्रचार, सोशल मीडिया पर शेयर कीं नेताओं की फोटो

2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूजा पाल को भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करते देखा गया था। इतना ही नहीं वे अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स से भी भाजपा नेताओं की तस्वीरें साझा करती रहती हैं। सीएम योगी ने भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूजा पाल का जिक्र करते हुए सपा पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने तंजात्मक अंदाज में कहा था, 'माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे की जाती है वो आप अपने ही पार्टी की विधायक पूजा पाल से पूछ सकते हैं। आपकी सरकार थी लेकिन आपने उन्हें न्याय नहीं दिया। बेटी चाहे इस पक्ष की हो या फिर सत्ता पक्ष की यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे न्याय मिले।'

सपा के पीडीए फॉर्मूले को साधेगी भाजपा ?

पूजा पाल के मंत्री बनने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वे सपा के पीडीए फार्मूला का हिस्सा हैं। दलित समाज से आने वाली पूजा पाल को मंत्री बनाकर बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर सवाल उठाना चाहती है।

छतरपुरः PM आवास योजना के पैसे जारी करने के लिए 5000 मांगे, अब घूसखोर सचिव को 3 साल की सजा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (लोकायुक्त) न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है. प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त जारी करने के बदले रिश्वत लेने के दोषी पाए गए ग्राम पंचायत कदारी के सचिव भरत वर्मा को अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला मंगलवार को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त आशीष श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया. यह मामला 18 मार्च 2019 का है. फरियादी जगत यादव ने सागर के लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि उनके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान की शेष राशि जारी करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव भरत वर्मा रिश्वत की मांग कर रहे थे. योजना के तहत फरियादी को कुल 1 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 1 लाख 20 हजार रुपये पहले ही उनके खाते में जमा हो चुके थे. शेष 30 हजार रुपये की किस्त जारी करने के बदले सचिव द्वारा 5 हजार रुपये की अवैध मांग की जा रही थी.

5 हजार रुपये घूस की मांग

शिकायत की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी की रिश्वत मांगने से जुड़ी बातचीत को 18 मार्च 2019 को वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया. रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से सचिव भरत वर्मा द्वारा 5 हजार रुपये की मांग करते हुए 1 हजार रुपये स्वीकार करने की पुष्टि हुई थी. आरोपी ने फरियादी से शेष 4 हजार रुपये अगले दिन लाने को कहा था. इसके बाद 19 मार्च 2019 को लोकायुक्त टीम ने ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया. योजना के अनुसार फरियादी को तय स्थान छतरपुर स्थित चौबे नर्सिंग होम के पास भेजा गया, जहां आरोपी सचिव ने शेष 4 हजार रुपये की रिश्वत ली. जैसे ही आरोपी ने राशि स्वीकार की, मौके पर मौजूद लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान रिश्वत की रकम आरोपी की पेंट की दाहिनी जेब से बरामद की गई. आरोपी के हाथों को सोडियम कार्बोनेट घोल में धुलवाया गया, जिससे घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया. यह परीक्षण रिश्वत लेने की वैज्ञानिक पुष्टि माना जाता है. जांच पूरी होने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक (एडीपीओ) अभिषेक मेहरोत्रा द्वारा की गई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत सभी साक्ष्य, दस्तावेज और गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दोषी करार दिया. अदालत ने भरत वर्मा को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देने वाला माना जा रहा है।

उद्देश्यहीन संयुक्त राष्ट्र संघ को भंग क्यों नही करते?

संयुक्त राष्ट्र संघ (यूनाइटेड नेशनस) का मुख्य औचित्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, और विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में 51 देशों द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भावी युद्धों को रोका वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। आज 193 देश इसके सदस्य हैं। इतने बड़े संगठन का लगता है कि आज कोई देश कहना मानने को तैयार नहीं। सबकी अपनी ढपली अपना राग है। संयुक्त राष्ट्र संघ तमाशबीन बन कर रह गया है। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जाकर लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया गया। उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया है। वहां ड्रग्स तस्करी के आरोपों में उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। अमेरिका इस पर भी ये चुप नहीं बैठा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य अभियान के बाद कई देशों को धमकी दी है। उन्होंने इशारा किया है कि कोलंबिया में कभी भी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने मेक्सिको को भी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि वह वेनेजुएला के बेपटरी हो चुके तेल उद्योग को उबारने के लिए अमेरिकी कंपनियों पर भरोसा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया कि वह कोलंबिया में सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेक्सिको को ड्रग्स के मामले में ठीक से काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। उधर वेनेजुएला की मौजूदा स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में महासचिव एंटेनियो गुटेरेस के बयान में कहा गया कि वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई के मामले में 'अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों का पालन नहीं किया गया है', इस बात से वे 'बहुत चिंतित' हैं। रोजमेरी डिकालों ने गुटेरेस का बयान पढ़ते हुए इस बात पर चिंता जताई कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए क्या मिसाल कायम कर सकती है।उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में हालात नाजुक हैं, लेकिन अभी भी एक बड़े टकराव को रोका जा सकता है। वहीं रूस के प्रतिनिधि ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को तुरंत रिहा करने की मांग की। ईरान के भी हालात ठीक नही है। वहां भी कभी भी तख्ता पल्ट हो सकता है। ईरान में बढ़ती महंगाई और देश की बिगड़ती आर्थिक हालत को लेकर सरकार के खिलाफ़ लगभग एक हफ्ते से प्रदर्शन जारी है।ये पिछले तीन साल में देश में सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल पर पोस्ट में ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को मदद का भरोसा भी दिया है। उन्होंने लिखा, 'अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और उन्हें बेरहमी से मारता है, जो कि उनकी आदत है, तो अमेरिका उनको (प्रदर्शनकारियों को) बचाने के लिए आएगा। 'अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के 'शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों' की मदद के लिए 'पूरी तरह तैयार' है। पिछले साल जून में अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। दावा किया गया कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। इस्राइल भी हमले कर चुका है। इस्राइल और अमेरिका की नजर में बहुत समय ये ईरान खटक रहा है। एक ओर अमेरिक की दादागिरी का ये हाल है। उधर चीन ताइवान पर कब्जा करने को तैयार बैठा है। वह समय- समय पर अपनी वायु और जल सेना भेजकर ताइवान को धमकाता रहता है। कभी भी चीन सैनिक कार्रवाई कर ताइवान पर कब्जा कर सकता है। इस्राइल और हमास के बीच सात अक्टूबर 2023 को शुरू हुए युद्ध को चलते हुए दो साल और तीन महीने हो चुके है। अक्टूबर 2025 में एक संघर्ष विराम समझौता हुआ था। इसके बाद बड़े पैमाने पर बमबारी में कमी आई है, लेकिन तनाव और छिटपुट सैन्य कार्रवाई अभी भी जारी है।गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, अब तक इस युद्ध में 70,000 से अधिक लोग मारे जा चुके है। इसमें हमास के लड़ाके और बड़ी संख्या में नागरिक (महिलाएं और बच्चे) शामिल हैं। 1,71,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इज़रायल पक्ष की ओर से सात अक्टूबर 2023 के हमले में लगभग 1,200 लोग मारे गए थे। इसके बाद सैन्य अभियान के दौरान लगभग 1,000+ इज़रायली सैनिक मारे गए है। इस युद्ध में गाजा पट्टी की लगभग 80 प्रतिशत इमारतें और बुनियादी ढांचा (अस्पताल, स्कूल, सड़कें) पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो चुके हैं। युद्ध के कारण इजरायल को अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है तो गाजा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इस्राइल से ईरान पर भी हमला किया। इसमें 'बैलिस्टिक मिजाइल प्रयोग हुआ। ईरान ही नही इस्राइल ने कतर पर भी पिछले दिनों हमला किया। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए रूस-यूक्रेन युद्ध को तीन साल 10 माह बीत गए। युद्ध निरंतर जारी है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ और पश्चिमी खुफिया रिपोर्टो के अनुसार, रूस के 12 लाख से अधिक सैनिक या तो मारे गए है या घायल हुए हैं। स्वतंत्र रूसी मीडिया समूहों ने ओपन-सोर्स डेटा के आधार पर कम से कम 1,53,000+ रूसी सैनिकों की मौत की होना माना है। विभिन्न पश्चिमी अनुमानों (जैसे दिसंबर 2024-25 की रिपोर्ट) के अनुसार, यूक्रेन के लगभग 4,00,000 से 5,00,000 सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। इतना सब हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव जीवन की बरबादी देख रहा है। यह असहाय बना बैठा है। मानव जीवन का विनाश रोकने के लिए वह कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी भूमिका शून्य होकर रह गई है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं कर सकता। कोई देश उसकी मानने को तैयार नही। युद्ध रोकने की उसकी शक्ति नहीं तो उसका औचित्य क्या है? दुनिया के देश क्यों इस सफेद हाथी को पाले है। क्यों इसका खर्च वहन कर रहे हैं। इसे भंग क्यों नही कर दिया जाता। लगभग दो साल पूर्व हमास- इस्राइल युद्ध को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रयास हुए। कई बार प्रस्ताव के प्रयास हुए पर वीटो पावर वाले देशों के अड़ंगे के कारण कुछ नहीं हो सका। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस युद्ध को रोकने के लिए सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार किया, किंतु इस्राइल ने इसे स्वीकार करने से मना कर इतना सब होने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को नहीं रोक पाया। न रोक पा रहा है। इस युद्ध से युद्धरत देशों के विकास तो रुका ही, मानव कल्याण के लिए भवन, पुल, स्कूल और उद्योग खंडहर बन गए। हमास -इस्राइल युद्ध के बीच हुति विद्रोहियों ने इस्राइल पर मिजाइल से हमले किए। इस्राइल समर्थक देशों के मालवाहक जहाजों पर मिजाइल दागीं। इस सब के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की नींद नही खुली। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा कुछ देश के हाथों की कठपुतली बन गया है। अन्य देश न अपनी ताकत का प्रयोग कर सकता है ना अपनी क्षमता का। आज के हालात को देखते हुए लगता है कि अपने सबसे बड़े कार्य का दायित्व निभाने में वह सक्षम नहीं है। पांच वीटो पावर देश उसे अपनी मर्जी से नचा रहे हैं। उनके एकजुट हुए बिना संयुक्त राष्ट्र महासभा कुछ नहीं कर सकता। ये पांचो विटो पावर देश खुद खेमों में बंटे है। ऐसे में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास होना एक प्रकार से नामुमकिन हो गया है। म्यांमार में पिछले दिनों सेना का जुल्म देखने को मिला। चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म जग जाहिर है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आज आतंकवाद पूरे विश्व की बड़ी समस्या है। सब जानते हैं कि कौन देश इसे पालपोस रहे हैं। इस आतंकवाद के खात्मे के लिए कोई संयुक्त प्रयास नही हो रहे। कभी इस बारे में प्रस्ताव आता है तो पांच विटो पावर दादाओं में से कोई न कोई उस प्रस्ताव को विटो कर देता है। आज जरूरत आ गई है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की उपयोगिता पर विचार किया जाए। इसे उपयोगी बनाने पर कार्य किया जाए। ऐसा ढांचा खड़ा किया जाए कि एक देश दूसरे देश का मददगार बने। मुसीबत में उसके साथ खड़े हो, उसकी रक्षा कर सकें। ऐसा नहीं कि लाठी के बूते कोई किसी देश की चुनी सरकार को अपदस्थ कर दे। सब दुनिया के सभी देश बराबर हैं ऐसा हो। पूरे दुनिया के पांच देशों को ही वीटो पावर का अधिकार क्यों? उनकी ही पूरी दुनिया पर दादागिरी क्यों?इस पर विचार किए जाने की जरूरत है।आज के हालात में सामूहिकता बढ़ाने ,सामूहिक निर्णय पर चलने, सामूहिक विकास का सोचने की सबसे बड़ी जरूरत है। एक ऐसे संगठन की दुनिया को जरूरत है जो निष्पक्ष और तटस्थ होकर पूरी दुनिया में शांति स्थापना के लिए काम कर सके।

अशोक मधुप

सभी परीक्षाओं में जैमर और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य हो

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा फरवरी-मार्च में आयोजित होने वाली दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने का नया निर्णय सराहनीय और दूरदर्शी है। बोर्ड ने संवेदनशील एवं अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल ऐप आधारित ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत जैमर और सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा प्रक्रिया पर सतत नजर रखी जाएगी। यह कदम न केवल परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बहाली का माध्यम भी बनेगा।तकनीक के दुरुपयोग से नकल के नए तरीके उभरे हैं—मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरपीस और सोशल मीडिया के जरिए संगठित गिरोह अब बड़ी चुनौती हैं। जैमर परीक्षा केंद्रों में मोबाइल नेटवर्क को निष्क्रिय करेगा, जबकि सीसीटीवी न केवल परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा, बल्कि कक्ष निरीक्षकों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को भी पारदर्शी बनाएगा। कैमरे लगाने से काम नहीं चलेगा; परीक्षा के दौरान उनकी सतत निगरानी और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई जरूरी है।यह व्यवस्था साहसिक इसलिए है क्योंकि अब तक अनियमितताओं का दोष मुख्यतः छात्रों पर ही मढ़ा जाता रहा, जबकि लापरवाही या मिलीभगत की शिकायतें भी आम हैं। सीसीटीवी से जवाबदेही तय होगी और ईमानदार शिक्षकों को संदेह से मुक्ति मिलेगी।मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा विभाग ने इसे फिलहाल केवल संवेदनशील केंद्रों तक सीमित रखा है, लेकिन इसे चरणबद्ध रूप से सभी परीक्षा केंद्रों पर लागू करना चाहिए। समान परीक्षा प्रणाली में भिन्न निगरानी स्तर असमानता पैदा करते हैं। यदि परीक्षा योग्यता और परिश्रम का सच्चा मूल्यांकन है, तो प्रक्रिया हर जगह निष्पक्ष होनी चाहिए।उच्च शिक्षा विभाग को भी आगे आना होगा। सरकारी-निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नकल की शिकायतें कम नहीं हैं। बोर्ड स्तर पर संभव तकनीकी निगरानी को उच्च शिक्षा में भी लागू कर विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक योग्यता के अनुरूप परिणाम सुनिश्चित किए जाएं।नकल मुक्त परीक्षा केवल प्रशासनिक सख्ती नहीं, बल्कि शिक्षा गुणवत्ता, सामाजिक नैतिकता और राष्ट्र निर्माण का मुद्दा है। मध्य प्रदेश का यह निर्णय पूर्ण प्रतिबद्धता से लागू हुआ, तो अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल बनेगा।

डा मनमोहन प्रकाश

कब लौटेगी मणिपुर में शांति की सुबह आईईडी धमाकों से टूटी खामोशी और सुलह की तलाश

मणिपुर एक बार फिर दहल उठा है। कुछ दिनों की अपेक्षाकृत शांति के बाद विष्णुपुर जिले में हुए आईईडी धमाकों ने न केवल लोगों के जख्म हरे कर दिए हैं बल्कि यह भी दिखा दिया है कि राज्य में हालात अब भी बेहद नाजुक हैं। तीन घंटे के भीतर दो विस्फोट और आम नागरिकों का घायल होना इस बात का संकेत है कि हिंसा का स्वरूप अब और खतरनाक दिशा में जा सकता है। 3 मई 2023 से शुरू हुई मैतेई और कुकी समुदायों के बीच की टकराहट पहले फायरिंग और आगजनी तक सीमित थी लेकिन अब आईईडी जैसे हथियारों का इस्तेमाल चिंता को कई गुना बढ़ा देता है। यह सिर्फ एक सुरक्षा घटना नहीं है बल्कि मणिपुर के सामाजिक तानेबाने पर एक और गहरी चोट है। मणिपुर का संकट केवल कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है बल्कि यह पहचान भूमि संसाधन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा जटिल मसला है। मैतेई समुदाय घाटी में बहुसंख्यक है और प्रशासनिक राजनीतिक ढांचे में उसका प्रभाव ऐतिहासिक रूप से अधिक रहा है। कुकी समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहता है और लंबे समय से यह आशंका जताता रहा है कि उसकी जमीन और पहचान पर खतरा बढ़ रहा है। आरक्षण और भूमि अधिकारों को लेकर उठे विवाद ने धीरे धीरे सामुदायिक अविश्वास को खुली हिंसा में बदल दिया। जब राज्य में संवाद की जगह हथियार बोलने लगें तो उसका असर केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरा समाज उसकी कीमत चुकाता है। आईईडी धमाके इस संघर्ष को एक नए और अधिक भयावह मोड़ पर ले जाते हैं। इससे पहले तक हिंसा की घटनाएं अपेक्षाकृत सीमित और स्थानीय थीं लेकिन विस्फोटक का प्रयोग यह संकेत देता है कि उग्र तत्व अब संगठित और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम हो रहे हैं। यदि इस प्रवृत्ति को समय रहते नहीं रोका गया तो मणिपुर का संकट राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता भी बन सकता है। ऐसे में किसी एक समुदाय को दोषी ठहराना आसान है लेकिन समाधान के लिहाज से यह सबसे कमजोर रास्ता भी है। मैतेई समुदाय के लिए यह संघर्ष भारी नुकसान लेकर आया है। घाटी क्षेत्र जो राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक रीढ़ है लंबे समय से अस्थिरता के कारण ठप पड़ा है। व्यापार पर्यटन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती और कर्फ्यू जैसे हालात ने सामान्य जीवन को बाधित कर दिया है। युवाओं में असुरक्षा और गुस्से की भावना बढ़ रही है जो उन्हें कट्टर सोच की ओर धकेल सकती है। यह स्थिति मैतेई समाज के लिए दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। कुकी समुदाय की पीड़ा भी कम नहीं है। पहाड़ी इलाकों में बसे कई गांव उजड़ चुके हैं। विस्थापन ने हजारों परिवारों को राहत शिविरों में रहने को मजबूर किया है। आजीविका के साधन छिन गए हैं और बच्चों की शिक्षा लगभग ठप हो गई है। कुकी समाज के भीतर यह भावना गहरी होती जा रही है कि राज्य और केंद्र की नीतियां उनकी सुरक्षा और अधिकारों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहीं। इस हताशा का फायदा उग्रवादी तत्व उठाते हैं और युवाओं को हिंसा के रास्ते पर ले जाते हैं। दोनों समुदायों के लिए यह संघर्ष किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। हिंसा ने न तो मैतेई को सुरक्षित बनाया है और न ही कुकी को सशक्त। उलटे इसने अविश्वास की ऐसी खाई बना दी है जिसे पाटना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। सामाजिक रिश्ते टूट रहे हैं मिश्रित बस्तियां खत्म हो रही हैं और साझा सांस्कृतिक विरासत पर खतरा मंडरा रहा है। मणिपुर जो कभी विविधताओं के बीच सहअस्तित्व का उदाहरण था आज भय और संदेह के माहौल में जी रहा है। सरकार और सुरक्षा बलों की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य में भारतीय सेना सीआरपीएफ बीएसएफ और असम राइफल्स जैसे बलों की बड़ी मौजूदगी है। हथियारों की बरामदगी और संवेदनशील इलाकों में गश्त से कुछ हद तक हालात काबू में रखे गए हैं लेकिन केवल सैन्य समाधान से स्थायी शांति संभव नहीं है। सुरक्षा बल आग को फैलने से रोक सकते हैं लेकिन बुझाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक संवाद जरूरी है। राजनीतिक शून्य भी मणिपुर की समस्या को गंभीर बना रहा है। पूर्ण और प्रभावी सरकार के अभाव में निर्णय प्रक्रिया कमजोर पड़ती है। जब लोगों को यह भरोसा नहीं होता कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वे वैकल्पिक और अक्सर हिंसक रास्ते चुन लेते हैं। केंद्र सरकार और राज्यपाल द्वारा किए जा रहे प्रयास तब तक अधूरे रहेंगे जब तक स्थानीय नेतृत्व को विश्वास में लेकर एक समावेशी राजनीतिक समाधान नहीं निकाला जाता। संवाद ही वह रास्ता है जो मणिपुर को इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। मैतेई और कुकी दोनों समुदायों को यह समझना होगा कि उनकी सुरक्षा और भविष्य एक दूसरे से जुड़ा है। एक की हार दूसरे की जीत नहीं बन सकती। भूमि अधिकार आरक्षण और प्रशासनिक संरचना जैसे मुद्दों पर खुली और ईमानदार बातचीत जरूरी है। इसके साथ ही उग्रवादी तत्वों को मुख्यधारा से अलग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि वे शांति प्रक्रिया को पटरी से न उतार सकें। सिविल सोसाइटी छात्रों और धार्मिक नेताओं की भूमिका भी अहम हो सकती है। विरोध प्रदर्शन और बंद से गुस्से की

अभिव्यक्ति तो होती है लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकलता। यदि यही ऊर्जा शांति और संवाद के लिए इस्तेमाल हो तो हालात बदल सकते हैं। मीडिया को भी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी ताकि किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत और अफवाहें न फैलें। मणिपुर में शांति का सवाल केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है। यह पूरे देश के लिए एक संदेश है कि विविधता वाले समाज में असहमति को कैसे संभाला जाए। यदि यहां सुलह का रास्ता निकलता है तो यह लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण बनेगा। यदि हिंसा यूं ही चलती रही तो यह देश की सामाजिक एकता पर गहरा असर डाल सकती है। आज मणिपुर के लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि वे कब चैन की सांस ले पाएंगे। इसका जवाब किसी एक घटना या एक फैसले में नहीं छिपा है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें भरोसा बहाल करना होगा जख्मों पर मरहम लगाना होगा और भविष्य के लिए साझा दृष्टि बनानी होगी। आईईडी धमाकों की गूंज भले कुछ पलों में थम जाए लेकिन उनसे उठने वाला सवाल लंबे समय तक गूंजता रहेगा कि क्या मणिपुर फिर से शांति की ओर लौट पाएगा। इसका उत्तर हिंसा नहीं बल्कि संवाद न्याय और राजनीतिक साहस में छिपा है।

कांतिलाल मांडोत

संपादकीय

आस्था के साए में अपराधः पैरोल ने फिर जगाए विवाद

[पैरोल के पर्दे में दबा न्याय और टूटता भरोसा]
[सजा के बाद भी बार-बार राहतः लोकतंत्र की कसौटी पर सवाल]

क्या न्याय सचमुच अंधा है, या वह अब प्रभाव, संख्या और आस्था को पहचानने लगा है। यह प्रश्न तब और तीखा हो उठा, जब डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर (15वीं बार) 40 दिनों की पैरोल (फरलो) पर जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई। यह केवल एक सजायाफ्ता व्यक्ति की अस्थायी रिहाई नहीं, बल्कि कानून की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक नैतिकता पर सीधा प्रहार था। जब गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध होने के बावजूद बार-बार राहत दी जाती है, तो समाज के भीतर यह संदेह गहराना स्वाभाविक है कि क्या न्याय वास्तव में सबके लिए समान है। यही बेचैन करने वाली शंका पूरे घटनाक्रम के केंद्र में खड़ी होकर नागरिक चेतना को भीतर तक झकझोर देती है। राम रहीम का नाम वर्षों से अपराध, आस्था और प्रभाव के विचित्र संगम का प्रतीक बन चुका है। महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों और एक निर्भीक पत्रकार की हत्या ने देश को भीतर तक हिला दिया था। न्यायालय द्वारा दी गई कठोर सजाओं से यह आशा जगी थी कि धर्म की आड़ में छिपे अपराधों पर अब कोई समझौता नहीं होगा। परंतु समय बीतने के साथ बार-बार मिली पैरोल ने उस भरोसे को कमजोर किया। स्वयं को आध्यात्मिक मार्गदर्शक बताने वाला व्यक्ति जब लगातार जेल से बाहर आता है, तो धर्म और अपराध के बीच खींची गई रेखा धुंधली पड़ने लगती है। पैरोल का सिद्धांत मानवीयता और सुधार से जुड़ा होता है। इसका उद्देश्य कैदी को समाज से जोड़े रखना और उसे आत्ममंथन का अवसर देना है। लेकिन राम रहीम के मामले में पैरोल एक अपवाद नहीं, बल्कि नियमित प्रक्रिया जैसी प्रतीत होने लगी है। सजा के सीमित वर्षों में कई बार बाहर आना और लंबा समय जेल से बाहर बिताना सामान्य कैदियों की स्थिति से बिल्कुल अलग है। यह प्रश्न उठता है कि नियमों की व्याख्या इतनी उदार क्यों है। जब राहत बार-बार और समय विशेष पर मिलती दिखे, तो कानून की मंशा पर संदेह होना स्वाभाविक है। न्याय की कसौटी पर यह स्थिति अत्यंत विचलित करने वाली है। एक ओर ऐसे लोग हैं, जिन पर आरोप अभी सिद्ध भी नहीं हुए, फिर भी वे वर्षों से कारावास झेल रहे हैं। दूसरी ओर सिद्ध अपराध के बावजूद बार-बार पैरोल दी जा रही है। यह विरोधाभास व्यवस्था के दोहरे मापदंड को साफ उजागर करता है। विशेषज्ञों के अनुसार नियमों की अस्पष्टता और प्रशासनिक विवेक की अत्यधिक छूट ने इस असमानता को जन्म दिया है। जब निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रहती, तब न्याय कागज़ों तक सिमट जाता है और जनता का भरोसा धीरे-धीरे दरकने लगता है। इस पूरे घटनाक्रम में सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े अनुयायी समूह अपने आप में शक्ति बन जाते हैं। यही शक्ति कई बार निर्णयों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव का कारण बनती है। धर्मस्थलों और धार्मिक व्यक्तित्वों का सामाजिक प्रभाव नई बात नहीं है, लेकिन जब इसका उपयोग कानून को नरम करने के लिए होने लगे, तो खतरा बढ़ जाता है। आस्था जब संगठित समर्थन में बदल जाती है, तो न्याय कमजोर पड़ने लगता है। यह प्रवृत्ति केवल एक मामले तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक लोकतांत्रिक चुनौती का संकेत है। धार्मिक पहलू इस विवाद को और अधिक संवेदनशील बना देता है। जब आस्था विवेक पर भारी पड़ती है, तब प्रश्न पूछने की क्षमता क्षीण हो जाती है और अंधभक्ति हावी होने लगती है। पैरोल के दौरान होने वाली गतिविधियां अनुयायियों में उत्साह और भरोसा भरती हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए वही क्षण गहरी पीड़ा का कारण बनते हैं। उनके लिए हर रिहाई न्याय के पुराने घावों को फिर से हरा कर देती है। धर्म का उद्देश्य नैतिक उत्थान और करुणा है, न कि अपराधों के लिए ढाल बनना। जब आस्था का उपयोग संरक्षण के लिए होता है, तो समाज में गलत संदेश जाता है। न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा और दूरगामी है। जब आम नागरिक यह देखता है कि प्रभावशाली नामों के लिए कानून के द्वार सहजता से खुल जाते हैं, तो न्याय के प्रति सम्मान स्वतः कमजोर पड़ने लगता है। सार्वजनिक विमर्श में दिखाई देने वाला

आक्रोश केवल क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भीतर तक जमी निराशा की अभिव्यक्ति है। लोग इसे सुविधा और प्रभाव से संचालित न्याय कहने लगे हैं। जब निर्णयों पर स्पष्ट, पारदर्शी और ठोस उत्तर नहीं मिलते, तब यह मौन अविश्वास को जन्म देता है। यदि समय रहते विश्वास बहाल नहीं किया गया, तो यह दरार स्थायी बनकर न्याय व्यवस्था की नींव को ही कमजोर कर देगी। सबसे गहरी पीड़ा पीड़ितों की है, जिनकी आवाज अक्सर भीड़ और शोर में दबकर रह जाती है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े प्रश्न केवल कानून तक सीमित नहीं, बल्कि समाज की नैतिक चेतना की भी परीक्षा हैं। जब दोष सिद्ध होने के बाद भी कठोरता नहीं दिखाई जाती, तो यह संदेश जाता है कि शक्ति ढाल बन सकती है। ऐसी सोच समाज को भीतर से कमजोर करती है, क्योंकि इससे अपराध सामान्य और न्याय सापेक्ष हो जाता है। कोई भी व्यवस्था तब तक मानवीय नहीं कही जा सकती, जब तक वह सबसे कमजोर के साथ समान और संवेदनशील व्यवहार न करे। राम रहीम की पैरोल का मुद्दा किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह धर्म, प्रभाव और कानून के उस खतरनाक मेल को उजागर करता है, जहां सीमाएं लगभग मिटती जा रही हैं। यहां सुधार केवल नियम बदलने से नहीं आएगा, बल्कि सोच और प्राथमिकताओं में मूलभूत परिवर्तन आवश्यक है। पारदर्शी मापदंड, कानून का समान अनुप्रयोग और स्पष्ट सार्वजनिक जवाबदेही ही टूटते विश्वास को जोड़ सकते हैं। अब समय आ गया है कि व्यवस्था आत्मपरीक्षण करे, क्योंकि जब न्याय से समझौता होता है, तो लोकतंत्र की नींव डगमगाने लगती है।

प्रो. आरके जैन

विश्व कानून को ताक पर रखकर अमेरिका की अराजकता

इसे अराजकता कहें या गुंडई वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी इस बात की तस्दीक करती है कैसे विश्व की हथियारों से लैस महाशक्तियां सिर्फ अपने निजी हितों के लिए नैतिकता को ताक पर रख कर अंतरराष्ट्रीय नियम कायदों को धता बताती है और कमजोर देश का गला दबा कर उसे अपना ओपनिवेश बनाने का प्रयास करते हैं। वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों तेल के बड़े भंडार पर अमेरिकी प्रभुत्व की लालसा, कमजोर देशों पर उसकी दादागिरी को उजागर किया है. वेनेजुएला संकट, एक तरह से तमाम अंतरराष्ट्रीय न्याय का हनन और 'पावर' का मनमाना दुरुपयोग है अमेरिका लंबे समय से दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो उसके सामने झुकने को तैयार नहीं थे। मादुरो पर अमेरिका में ड्रग का धंधा या नार्को टेररिज्म बढ़ाने का आरोप लगाकर ट्रंप ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास सहित कई शहरों पर हवाई हमला करवाया। अमेरिकी फौज ने मादुरो व उनकी पत्नी को आधी रात में घसीटकर बाहर निकाला और गिरफ्तार किया, वह उन्हें न्यूयॉर्क ले जाएगी, जहां उन पर नशे के व्यापार पर केस चलेगा और सजा होगी। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला में फिलहाल अमेरिका ही सत्ता संभालेगा। इसी तरह 3 दशक पूर्व अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रोगन ने अपने देश में नशे का कारोबार फैलाने के आरोप में पनामा के राष्ट्रपति नरेगा को गिरफ्तार कर उम्रकैद की सजा दी थी। अमेरिकी सीक्रेट एजेंट पनामा से नरेगा को पकड़कर अमेरिका लाए थे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि वह भी इतने शक्तिसंपन्न हैं कि किसी देश के राष्ट्रपति को भी मुश्कें बांधकर अपने यहां ला सकते हैं। अब डर है कि कहीं वह मेक्सिको पर भी ऐसी कार्रवाई न करें क्योंकि वहां से बड़ी तादाद में अवैध प्रवासी अमेरिका में घुसपैठ करते हैं। ट्रंप ने पिछली बार मेक्सिको बॉर्डर पर ऊंची दीवार बनाने की बात कही थी। इसी प्रकार डेनमार्क की नाराजगी की परवाह न करते हुए ट्रंप ग्रीनलैंड पर भी कब्जा कर सकते हैं। अमेरिका ने इराक पर हमला करने के लिए सद्दाम हुसैन पर आरोप लगाया था कि वह केमिकल व बायोलॉजिकल शस्त्र बना रहे हैं। सद्दाम का सफाया कर दिया गया, लेकिन ऐसा कोई शस्त्र वहां नहीं पाया गया। अमेरिका ने ईरान की तेल कंपनियों पर अपना कब्जाबरकरार रखने के लिए वहां के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मुसद्दिक की हत्या करवाई थी और ईरान के शाह रजा पहलवी को वहां का शासन सौंपा था। ब्रिटेन की आयरन लेडी कहलाने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री मारग्रेट चैचर ने अपने देश से बहुत दूर फाकलैंड द्वीप पर कब्जा दिखाने के लिए अर्जेंटीना से युद्ध किया था। इस वॉर में ब्रिटेन के काफी संसाधन खर्च हुए थे। ऐसी ही अकड़ के चलते रूस-यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसने पुतिन के मास्को स्थित सरकारी निवास पर हवाई हमला किया। जब रूस की वायुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत है तो वहां यूक्रेन का मिसाइल या ड्रोन कैसे आ सकता है? असली बात यह है कि हमले का बहाना खोजने के लिए मनमाने आरोप लगाए जाते हैं। वैश्वीकरण की गति को धीमा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित विश्व के अन्य देशों पर टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध को स्थिति पैदा कर दी। ट्रंप प्रशासन उन अनेक बहुपक्षीय संस्थाओं की या तो फंडिंग कम कर रहा है या उनसे बाहर निकलने की धमकियां देकर उनकी भूमिका को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है, जो कथित तौर पर अमेरिका के हित में कार्य नहीं कर रही हैं। उनकी इस नीति का असर केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के भीतर भी इसका व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है।व्यापार युद्ध ने न केवल विदेशी व्यापार को झटका दिया है, बल्कि अमेरिका के घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि को भी बढ़ावा दिया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के प्रतिरोध में अन्य देशों द्वारा लगाए जाने वाले जवाबी टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है। अमेरिका में न सिर्फ रोजमर्रा की वस्तुएं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खिलौने, कपड़े, मशीनें आदि के महंगे होने से अमेरिका में मार्च 2025 के बाद से आयातित सामान की कीमतें लगभग चार प्रतिशत बढ़ी हैं, जबकि घरेलू सामान की कीमतें लगभग दो प्रतिशत बढ़ गई हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ट्रंप ने 200 से अधिक वस्तुओं पर से टैरिफ कम करने का फैसला किया है। अमेरिका में उद्योगों के लिए कच्चा माल महंगा होने से बढ़ती उत्पादन लागत से नौकरियां ही नहीं घट रही हैं, बल्कि किसानों की आय पर भी गहरा असर पड़ रहा है। चीन, कनाडा और यूरोपीय देशों द्वारा प्रतिशोध में लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिकी सोया और मक्का जैसी कृषि वस्तुओं की मांग घाटी है, जिससे किसानों की आय में गिरावट आने से सरकार को अरबों डालर को सब्सिडी देनी पड़ रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसके दुष्परिणाम अब स्पष्ट दिखने लगे हैं। येल विश्वविद्यालय के बजट अध्ययन केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, टैरिफ और विदेशी प्रतिकारात्मक करों के कारण 2025 में अमेरिका की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर लगभग 0.9 प्रतिशत अंक कम हो रही है। टैरिफ नीतियों के कारण एक आम अमेरिकी परिवार को औसतन 3,800 डालर तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं पेन-वार्टन बजट माडल का विश्लेषण बताता है कि ट्रंप की व्यापारिक नीतियों के कारण अमेरिका की जीडीपी दीर्घकाल में लगभग छह प्रतिशत तक घट सकती है और मजदूरी में लगभग पांच प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। ओईसीडी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि यदि टैरिफ और एकतरफा व्यापार नौतियां जारी रहीं तो 2026 तक अमेरिका की जीडीपी वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत

तक गिर सकती है। यह गिरावट न केवल अमेरिका, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी चिंता का कारण होगी, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार का मुख्य इंजन है। आम अमेरिकी इस नीतिगत बदलाव की सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। उच्य मूल्य, घटती आय और रोजगार के अवसरों में कमी ने अमेरिकी सपने को धारणा को कमजोर किया है। ट्रंप की मनमानी नीतियों का अमेरिका में विरोध भी शुरू हो चुका है। एक हालिया सर्वेक्षण में लगभग 55 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि ट्रंप अब एक खतरनाक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वह अपने विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में अमेरिका का लोकतांत्रिक ढांचा पहले की अपेक्षा अधिक विभाजित हो गया है। 'हंड्स आफ' और 'नो किंग' जैसे आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी जनता अब अधिक हस्तक्षेप और केंद्रीकृत शाक्ति के विरोध में एकजुट हो हो रही है। हिचकोले खा रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ट्रंप की राष्ट्रवादी नीतियां और अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो रही हैं। 'अमेरिका प्रथम' के उनके नारे ने जहां कुछ समय के लिए घरेलू उद्योगों को सहारा दिया, वहीं वैश्विक व्यापारिक साझेदारियों से दूरी ने अमेरिकी बाजार पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अंतरराष्ट्रीय निवेश घटा है,निर्यात पर दबाव बढ़ा है और डालर की अस्थिरता से आयात महंगा हुआ है। यहां बता देंकि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो, जो वेनेजुएला में विपक्ष की प्रमुख नेता हैं, ने अंतरिम राष्ट्रपति के पद पर रोड्रिगेज़ की नियुक्ति को नकार दिया है। मचाडो ने दो-टूक सुना दिया है कि वह रोड्रिगेज़ को वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नहीं मानेंगी। गौरतलब है कि मचाडो फिलहाल निर्वासन में हैं लेकिन जल्द ही देश वापस लौटने की योजना बना रही हैं। गौरतलब है कि मादुरो की किडनैपिंग के बाद मचाडो को वेनेजुएला की अगली राष्ट्रपति बनने का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था। उन्हें ट्रंप का समर्थक भी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने उन्हें देश की नई अंतरिम राष्ट्रपति बनाने पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। बहरहाल दुनिया अमेरिका की दादागिरी पर स्तब्ध है।

मनोज कुमार अग्रवाल

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

रायबरेलीः नववर्ष की रात थाने के निकट चाकूबाजी की वारदात में पुलिस पर लापरवाही का आरोप

मुकदमा दर्ज होने में 24 घंटे की देरी; पीड़ित पक्ष ने SP से की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग

रायबरेली। नववर्ष की रात थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के चौहान मार्केट में हुई चाकूबाजी की घटना में पुलिस की त्वरित कार्रवाई न होने से पीड़ित पक्ष में आक्रोश है। हमलावरों द्वारा चाकू से किए गए जानलेवा हमले में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन मुकदमा दर्ज करने में 24 घंटे से अधिक का विलंब हुआ और आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक रायबरेली से नामजद अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। घटना 31 दिसंबर 2025 की रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि मुकदमा 2 जनवरी 2026 को शाम करीब 5 बजे दर्ज किया गया, जबकि घटना की सूचना तुरंत डायल 112 और थाने में दी गई थी। पुलिस पर आरोप है कि मात्र खानापूर्ति के लिए मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि त्वरित कार्रवाई नहीं की गई।

तालाब से अवैध कब्जा हटाने का आदेश, कब्जेदार पर अर्थदंड

लालगंज (रायबरेली)। तहसीलदार न्यायालय ने क्षेत्र के छमनीखेड़ा मजरे मुर्दीपुर मझिगवां गांव स्थित तालाब पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही अवैध कब्जेदार पर अर्थदंड भी लगाया गया है। ग्रामसभा के अभिलेखों में यह भूमि गाटा संख्या 46 के रूप में तालाब दर्ज है। गांव निवासी चंद्रिका प्रसाद द्वारा तालाब की भूमि पर भवन निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिससे तालाब का अस्तित्व समाप्त होने के साथ-साथ जल संरक्षण व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने मामले की जांच कराई, जिसमें कब्जा पूरी तरह अवैध पाया गया। इसके बाद प्रशासन की ओर से कब्जेदार को कई बार नोटिस जारी कर स्वयं कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया, लेकिन उसने आदेश की अवहेलना की। अंततः 15 नवंबर 2019 को हल्का लेखपाल द्वारा तहसीलदार न्यायालय में वाद दर्ज कराया गया। लंबी सुनवाई एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश देते हुए कब्जेदार पर अर्थदंड भी अधिरोपित किया। इस संबंध में एसडीएम मिथलेश त्रिपाठी ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मतदाता सूची का औपचारिक प्रकाशन, युवाओं को किया गया जागरूक

लालगंज (रायबरेली)। विधानसभा क्षेत्र 179 हरचंदपुर के अंतर्गत मंगलवार को सभी मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची का औपचारिक प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने का अवसर भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी मिथलेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में विकासखंड खीरों स्थित श्री सूरजदत्त कांति देवी पीजी कॉलेज में स्वीप (सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिक से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अवैध चाकू के साथ युवक गिरफ्तार

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के डलमऊ रोड बाईपास ओवरब्रिज के पास सोमवार को पुलिस ने एक युवक को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि सघन तलाशी अभियान के दौरान बन्नामऊ गांव निवासी शिवप्रताप सिंह को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

गोपाल बाग में भाकियू का धरना, सिंचाई संकट और गन्ना उतरवाई में अवैध वसूली पर उबाल

● रघु बाबा समाज सेवा संस्थान ने नहरों की स्थलीय जांच व दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोंडा। किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर गोपाल बाग में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के जिलाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में किसानों ने धरना-प्रदर्शन किया। धरने में किसानों ने एक ओर जहां नहरों के माइनरों में टेलगूल तक पानी न पहुंचने का मुद्दा उठाया, वहीं दूसरी ओर गन्ना उतरवाई में हो रही अवैध वसूली को लेकर प्रशासन और संबंधित विभागों पर गंभीर आरोप लगाए। किसानों ने बताया कि सरजू नहर खंड-4 से जुड़ी माइनरों में पानी आपूर्ति को लेकर अधिकारी बैठकों और पंचायतों में टेल तक पानी पहुंचने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। किसानों का कहना है कि दो हजार रुपये में जमीन दी गई थी, इस भरोसे के साथ कि सिंचाई सुविधा मिलेगी, लेकिन आज तक नहर का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा। केवल दिखावे के लिए कुछ दूरी तक पानी छोड़ा जाता है, जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। धरने में किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि पानी की किल्लत के बीच गन्ना उतरवाई के नाम पर ठेकेदारों व दलालों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है।

पैसा न देने पर गन्ना उठान में जानबूझकर देरी की जाती है, जिससे खेतों में खड़ा गन्ना खराब हो रहा है और किसान आर्थिक रूप से टूटते जा रहे हैं। इस मौके पर रघु बाबा समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार दूबे ने कहा कि जिन-जिन अधिकारियों द्वारा नहरों और माइनरों के टेलगूल तक पानी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, उनकी स्थलीय जांच कराई जानी चाहिए। यदि जांच में यह स्पष्ट होता है कि दावे गलत हैं और किसानों को गुमराह किया जा रहा है, तो ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। भाकियू जिलाध्यक्ष और अन्य किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही टेल तक पानी पहुंचाने, गन्ना उतरवाई की पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और अवैध वसूली पर रोक नहीं लगाई गई, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। किसानों ने साफ कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। धरना-प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल देखी जा रही है, जबकि किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उनका संघर्ष जारी।

निगोहां में आज पांचवें ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट होगा आगाज,डिप्टी सीएम करेंगे शुभारम्भ

● निगोहां कस्बे के एसएनटी मैदान में आयोजित ग्राम सभा क्रिक्रेट टूनामेंट का डिप्टी सीएम बृजेश पाठक करेंगे शुभारम्भ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज। निगोहां कस्बे में खेल प्रेमियों के लिए उत्सव का माहौल बन गया है।आज पांचवें ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट-2026 का भव्य शुभारंभ होगा।इस ऐतिहासिक खेल आयोजन का उद्घाटन प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि व्यापार मंडल अध्यक्ष सुरेन्द्र दीक्षित एवं भाजपा नेता अविचल शुक्ला मौजूद रहेंगे। आयोजक आशुतोष तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि निगोहां स्थित एस.एन.टी. मैदान में बुधवार सुबह 10 बजे से टूर्नामेंट का भव्य आगाज होगा। उद्घाटन अवसर पर खिलाड़ियों से परिचय, खेल भावना को समर्पित संदेश और औपचारिक उद्घाटन मैच भी आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आसपास जिलो के गांवों की कई मजबूत टीमें प्रतिभाग करेंगी, जिससे मुकाबले रोमांचक होने की उम्मीद है।यह आयोजन ग्राम प्रधान अभय कान्त दीक्षित समेत ग्रामीणों के सहयोग से कराया जा रहा है।आयोजकों का कहना है कि इस तरह के खेल आयोजनों से ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच मिलता है।टूर्नामेंट के समापन पर विजेता व उपविजेता टीमों को आकर्षक पुरस्कार व ट्रॉफी प्रदान की जाएंग।टूनामेंट का समापन 15जनवरी को होगा।

कोहरे ने थामी ट्रेनों और उड़ानों की रफ्तार, नहीं सुधरा गोरखधाम एक्सप्रेस का संचालन; शताब्दी एक्सप्रेस भी 2:20 घंटे लेट

लखनऊ। कोहरे और खराब मौसम के कारण मंगलवार को भी लखनऊ आने वाली रेल सेवाएं प्रभावित रहीं। उड़ान सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा और इंटरनेशनल के साथ घरेलू उड़ानों के लेट होने से यात्री एयरपोर्ट पर परेशान रहें। पिछले कई दिनों से गोरखधाम एक्सप्रेस की लेट लतीफी अब तक नहीं सुधर सकी है। नई दिल्ली के बाद कानपुर और उन्नाव ठहराव वाली गोरखधाम एक्सप्रेस मंगलवार को 8:39 घंटे की देरी से पहुंच सकी। वीआइपी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस भी 2:20 घंटे की देरी से लखनऊ आयी। इसके चलते पीछे आ रही आगरा फोर्ट लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी भी फंसी रही। यह ट्रेन 2:35 घंटे की देरी से मानकनगर स्टेशन पहुंच सकी। लखनऊ मेल, एसी एक्सप्रेस सहित करीब दो दर्जन ट्रेनें तय समय की जगह देरी से लखनऊ पहुंचीं। वहीं चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की दो दर्जन उड़ानें भी लेट लतीफी का शिकार हुईं।

लखनऊ बार एसोसिएशन हाल में वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैयालाल गौतम का हर्षोल्लास से मनाया जन्मदिन

● ..... 'वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैयालाल गौतम अधिवक्ताओं के अत्यंत शुभचिंतक हैं' – अधिवक्ता अनुज बाजपेई ।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विधि जगत की प्रतिष्ठित हस्ती कन्हैयालाल गौतम का जन्मदिन लखनऊ बार एसोसिएशन के हाल में हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ता, साथीगण तथा उनके शुभचिंतक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान 'जन्मदिन की शुभकामनाएं' के नारों से पूरा हाल गूंज उठा। समारोह के दौरान लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष (मध्य) पद के प्रत्याशी अधिवक्ता अनुज बाजपेई ने कन्हैयालाल गौतम को भव्य माला पहनाकर सम्मानित किया तथा भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्मृति-चिह्न स्वरूप भेंट कर उन्हें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अधिवक्ताओं के बीच मिठाइयों का वितरण भी किया गया। अधिवक्ता अनुज बाजपेई ने अपने संबोधन में कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैयालाल गौतम अधिवक्ताओं के अत्यंत शुभचिंतक हैं। वे सदैव युवा अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं तथा उनके हितों के संरक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका दीर्घ अनुभव, सरल स्वभाव और सहयोगी भावना बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रेरणास्रोत है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अन्य अधिवक्ताओं ने भी गौतम के न्यायप्रिय व्यक्तित्व, विधि क्षेत्र में उनके दीर्घकालीन योगदान तथा बार एसोसिएशन के प्रति उनकी निष्ठा की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस अवसर पर केक काटा गया तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर सभी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। नवीन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में अधिवक्ता रंजीत कुमार शर्मा, नरेंद्र कुमार साहू, ऐश्वर्य पांडे, काशान अंसारी, अंजलि कटियार, वसीमा खान सहित अनेक अधिवक्ता गण उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान आत्मीयता एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा। उपस्थित सभी लोगों ने कन्हैयालाल गौतम के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अंत में वरिष्ठ अधिवक्ता कन्हैयालाल गौतम ने सभी उपस्थित अधिवक्ताओं एवं शुभचिंतकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लखनऊ बार एसोसिएशन उनके लिए परिवार के समान है और यहां से मिला स्नेह एवं सम्मान उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

सीसी रोड निर्माण में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने सौंपा शिकायत पत्र

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- कुरारा विकास खंड के ककरऊ गांव में सीसी रोड निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा, जिससे भविष्य में आवागमन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

ग्रामीणों सुनील, कमल, शिवेंद्र सिंह, मोहित, शरमन, अभिलाष, ताजमोहम्मद और रवि दीक्षित ने शिकायत पत्र में बताया कि गांव में जिस मार्ग पर सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है, वहां एक छोटी पुलिया का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। पुलिया के अभाव में बरसात के समय पानी भरने और रास्ता क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है, बावजूद इसके पुलिया का निर्माण नहीं किया जा रहा। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सीसी रोड के दोनों किनारों पर नियमानुसार ईंटें नहीं लगाई जा रही हैं। इसके स्थान पर कच्चे रास्ते पर केवल गिट्टी डालकर ही सीसी रोड का कार्य शुरू कर दिया गया है, जो निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों की मांग है कि पहले पुलिया का निर्माण कराया जाए, उसके बाद ही सीसी रोड का कार्य पूरा किया जाए। इस संबंध में ग्राम प्रधान रामलखन और निर्माण कार्य देख रहीं इंजीनियर अंजलि ने बताया कि पुलिया का निर्माण स्वीकृत एस्टीमेट में शामिल नहीं है। इसी कारण कार्य को रोक दिया गया है और निर्माण सामग्री को अन्यत्र ले जाने की तैयारी की जा रही है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग जनहित से जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की जांच कराकर मानक के अनुसार पुलिया सहित सीसी रोड निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित और टिकाऊ सड़क सुविधा मिल सके।

बंगाल के संदेशखाली में पुलिस पर हुआ था हमला, मुख्य आरोपी TMC कार्यकर्ता मूसा मोल्ला गिरफ्तार

नई दिल्ली। पुलिस ने उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में पुलिस पर हुए हमले के मुख्य आरोपित मूसा मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। उसे मंगलवार को नैजाट पुलिस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वह इलाके में तृणमूल कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। इस घटना में मूसा से जुड़े अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मूसा पर जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप था। इसी आरोप के आधार पर अदालत ने उस जमीन पर धारा 144 लागू कर दी थी। जमीन पर किसी भी तरह का काम करना प्रतिबंधित था। आरोप है कि मूसा ने गत शुक्रवार रात को इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए उस जमीन पर दीवार बनाना शुरू कर दिया।

कैसे किया था पुलिस पर हमला?

सूचना मिलते ही राजबाड़ी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस मूसा के घर भी गई और उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहा। इसके बाद मूसा ने अपने समर्थकों को बुलाया और पुलिस पर हमला कर दिया। इस घटना में चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को इस घटना में नौ लोगों को गिरफ्तार किया। रविवार को तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों में मूसा का भाई मुर्तजा मोल्ला भी शामिल है।

मतदाता सूची का औपचारिक प्रकाशन, युवाओं को किया गया जागरूक

लालगंज (रायबरेली)। विधानसभा क्षेत्र 179 हरचंदपुर के अंतर्गत मंगलवार को सभी मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची का औपचारिक प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने का अवसर भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी मिथलेश त्रिपाठी की अध्यक्षता में विकासखंड खीरों स्थित श्री सूरजदत्त कांति देवी पीजी कॉलेज में स्वीप (सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं से अपील की कि वे समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अधिक से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

डीएम ने निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन कर मतदाता पंजीकरण का किया शुभारम्भ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2025-26 के अन्तर्गत अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के संबंध में जनपद में अवस्थित 06 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 177-बछरावां (अ0जा0) 179-हरचन्दपुर, 180-रायबरेली, 181-सलोन (अ0जा0), 182-सरेनी एवं 183-ऊँचाहार के मतदेय स्थलों पर निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया गया। इसी क्रम में जनपद स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गोरा बाजार रायबरेली में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। आई0टी0आई0 की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने 05 छात्राओं को फार्म-06 प्रदान कर मतदाता पंजीकरण का शुभारम्भ किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जनपद में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एस0आई0आर0) कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त कार्य ससमय पूर्ण किये गये है। इसी क्रम में आज जनपद की समस्त विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचनक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन कर मतदाता पंजीकरण का शुभारम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी युवा है जिन्होंने 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वह सभी अपना मतदाता पंजीकरण अवश्य कराये, आज का युवा हमारा भविष्य है। इसलिये मतदाता, पंजीकरण कराकर अपने मताधिकार को सुरक्षित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंजूलता, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा, उप जिलाधिकारी विवेक राजपूत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह, तहसीलदार सदर आकृति श्रीवास्तव, प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी फिरोज अहमद सहित सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

संविदा कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में एकदिवसीय सत्याग्रह, लखनऊ लेसा में सौंपा गया ज्ञापन

● .....वेतन वृद्धि, छंटनी पर रोक और सेवा सुरक्षा की मांग, चेतावनी–मांगे न मानी गईं तो होगा व्यापक आंदोलन ।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। विद्युत संविदा कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी, श्रम कानूनों के उल्लंघन और लगातार की जा रही छंटनी के विरोध में विद्युत संविदा मजदूर संगठन, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मंगलवार 6 जनवरी 2025 को प्रदेश के सभी जनपदों में एकदिवसीय सत्याग्रह आयोजित किया गया। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के लेसा (LESA) क्षेत्र में भी संविदा कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर अपनी मांगों को बुलंद किया। इस दौरान लेसा प्रभारी माता प्रसाद पांडे द्वारा अधीक्षण अभियंता के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संविदा कर्मचारियों की 11 सूत्री प्रमुख मांगों को प्रमुखता से रखा गया, जिसमें संविदा श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 22,000 तथा लाइनमैन, एसएसओ और कंप्यूटर ऑपरेटर का वेतन 25,000 किए जाने, पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने, संविदा कर्मचारियों की छंटनी बंद कर हटाए गए कर्मियों को पुनः कार्य पर लेने की मांग शामिल है। इसके साथ ही वर्ष 2023 की हड़ताल के दौरान कार्य करने के बावजूद हटाए गए संविदा कर्मियों को बहाल करने, संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाने और विभाग द्वारा सीधे भुगतान की व्यवस्था लागू करने, सेवानिवृत्ति आयु 55 से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने, दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में ?20 लाख का बीमा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, लक्ष्य प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने तथा फील्ड कर्मचारियों के लिए लागू फेसियल अटेंडेंस आदेश को वापस लेने की मांग भी उठाई गई। सत्याग्रह के दौरान मीडिया प्रभारी विमल चंद्र पांडे ने बताया कि इस आंदोलन में विद्युत संविदा मजदूर संगठन के प्रभारी पुनीत राय, विद्युत मजदूर संगठन के कोषाध्यक्ष एस.के. सिंह सहित रजनीश शर्मा, आकाश मिश्रा, अनूप सिंह, मानस मिश्रा, शिव कुमार, गुड्डू मिश्रा, पंकज कुमार समेत बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि संविदा कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक व तेज किया जाएगा।

बलिया में 476 अनफिट स्कूल वाहन होंगे सीजःसड़क से अतिक्रमण हटाने का एक सप्ताह का अल्टीमेटम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बलिया में जिला सड़क सुरक्षा समिति और जिला विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और स्कूल वाहनों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में कुल 338 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1644 स्कूल वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 1168 वाहन फिट पाए गए, जबकि 28 विद्यालयों के 476 स्कूल वाहन अनफिट घोषित किए गए। जिलाधिकारी ने आरटीओ को सख्त निर्देश दिए कि संबंधित 28 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक कर नोटिस जारी किया जाए और इन अनफिट वाहनों को सीज किया जाए। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिशासी अभियंता को जिले की सभी प्रमुख सड़कों पर डिवाइडर और सफेद लाइनिंग अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। साथ ही, सड़क डिवाइडरों पर किए गए अनावश्यक कट को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए। उन्होंने शहर के प्रमुख चौराहों और मुख्य सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे तथा होर्डिंग लगाने के भी निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी को शहर के प्रमुख चौराहों और सड़कों की पटरियों से अतिक्रमण को लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचना देकर एक सप्ताह के भीतर हटवाने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, सभी स्कूल वाहनों के पीछे ड्राइवर और विद्यालय के प्रधानाचार्य का मोबाइल नंबर अंकित करने के निर्देश दिए गए। अनफिट स्कूल वाहनों के खिलाफ प्रचार-प्रसार और विशेष अभियान चलाने को कहा गया, ताकि अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर जानकारी मिल सके। सभी स्कूल वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने आरटीओ को सड़क सुरक्षा पर स्कूल वाहन चालकों का प्रशिक्षण किसी बड़े विद्यालय में आयोजित कराने का निर्देश दिया। वहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रार्थना सभा के समय छात्रों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने तथा सड़क सुरक्षा से जुड़ी सभी गाइडलाइनों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। बैठक में आरटीओ अरुण कुमार राय, बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र गुप्ता, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

वन विभाग-वन माफिया गठजोड़ का आरोप, नहर किनारे हरे पेड़ों पर चला आरा

● ग्रामीणों के वीडियो से खुला मामला, लकड़ी व वाहन बरामद, एक आरोपी हिरासत में

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

गोंडा। नहर किनारे खड़े हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटान का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि वन विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों और सक्रिय वन माफिया की कथित मिलीभगत से नहर की हरित पट्टी में खुलेआम पेड़ों पर आरा चलाया जा रहा था। यह अवैध गतिविधि उस समय उजागर हुई, जब ग्रामीणों ने कटान का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वहीं, अवैध रूप से काटी गई लकड़ी और उसे ले जाने में प्रयुक्त वाहन को भी मौके से बरामद कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में वन दरोगा इंद्रजीत मौर्या ने बताया कि मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए लकड़ी तथा वाहन को जब्त कर लिया गया है और वन अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना विभागीय संरक्षण के इस तरह की बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटान संभव नहीं है। उनका कहना है कि नहर किनारे की हरियाली लगातार खत्म की जा रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस और वन विभाग की कार्रवाई से वन माफिया में खलबली मची हुई है। जांच पूरी होने के बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

संक्षिप्त खबरें

एसडीएम ने फीता काटकर वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष का किया शुभारंभ

हमीरपुर :- मंगलवार के दिन मौदहा कस्बा के रहमानियां इंटर कालेज में उपजिलाधिकारी करनवीर सिंह, तहसीलदार शेखर मिश्रा एवं कालेज प्रधानाचार्य डॉ रज़िया सुल्ताना ने कालेज में स्थापित वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष का फीता काटकर शुभारंभ किया। बताते चलें की भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किए गए विशेष पुनरीक्षण पंजीकरण कार्यक्रम जिसमें 1 जनवरी 2026 को या उससे पहले 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके नये मतदाताओं को मतदाता सूची अपना नाम दर्ज कराने हेतु शुरू किए गए अभियान के तहत नगर के रहमानिया इंटर कालेज में इस अभियान का शुभारंभ हुआ। जिसमे उपजिलाधिकारी ने कालेज में उपस्थित पुराने एवं नये मतदाताओं को जागरूक करने के साथ बीएलओ कक्ष का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान सम्बंधित बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान सदर लेखपाल अवनीश कुमार सहित समाजसेवी एवं सम्बंधित वार्ड के बीएलओ उपस्थित रहे।

मानसिक रोगों की पहचान और उपचार हेतु आयोजित किया जागरूकता स्वास्थ्य शिविर

हमीरपुर :- मौदहा सीएचसी में मंगलवार को मानसिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ।जिसमें बताया गया है कि मानसिक रोग दैविक प्रकोप भूत प्रेत जादू टोना या टोटका से नहीं होता है , इसका इलाज कराएं। झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े मानसिक रोग विशेषज्ञ की रैली मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है। शिविर में मरीज का निशुल्क प्रशिक्षण व उपचार उपलब्ध दावों का निशुल्क वितरण मरीज वहां परिवार जनों का काउंसलिंग दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना जन समस्या को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। बताया कि चिंता उलझन रहना ,नींद नहीं आना, अपने आप में खोए रहना एक ही विचार बार-बार आना एकाग्रता में कमी आना नशे की लत पादना ज्यादा साफ सफाई करना ऐसी तमाम लक्षण मानसिक रोगों की हो सकते हैं ।इस मौके पर डॉक्टर नीता डॉक्टर मुकेश गुप्ता अधीक्षक डॉक्टर रजत रंजन तिवारी डॉक्टर शानिब शाहिद शायद बड़ी संख्या में मरीज मौजूद रहे हैं।

मकान से सटा टूटा बिजली पोल बना जानलेवा, हर वक्त हादसे की आशंका

सुमेरपुर (हमीरपुर)। कस्बे के वार्ड संख्या 12 में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। यहां अखिलेश पालीवाल के मकान के बगल में लगा विद्युत पोल नीचे से टूटकर सीधे मकान की दीवार से टिक गया है। पोल पर लगी मोटी बिजली की केबल भी हवा में झूल रही है, जिससे किसी भी समय मकान में करंट उतरने का खतरा बना हुआ है। परिवार के लोग भय के साये में रहने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, जिस स्थान पर यह पोल टूटा है, वह रास्ता रोजमर्रा की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुबह-शाम इस मार्ग से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं गुजरते हैं। ऐसे में बिजली के खुले तारों से करंट फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। क्षेत्रीय वाशिंदों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति गलती से पोल या लटकी केबल के संपर्क में आ गया, तो गंभीर हादसा हो सकता है। लोगों ने बताया कि यह विद्युत पोल काफी समय से जर्जर हालत में था। इसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। समय रहते पोल नहीं बदला गया, जिसके चलते अब यह पूरी तरह से टूटकर मकान की दीवार से सट गया है। बारिश के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो सकती है, क्योंकि पानी के संपर्क में आने से करंट फैलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। स्थानीय निवासियों ने यह भी आशंका जताई है कि टूटे पोल का सहारा लेकर कोई असामाजिक तत्व मकानों तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे चोरी या अन्य आपराधिक घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इससे मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही वाशिंदों ने विद्युत विभाग से तत्काल टूटे पोल को हटाकर नया पोल लगाए जाने और बिजली आपूर्ति को सुरक्षित करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद रखी जाए। समाचार लिखे जाने तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। क्षेत्रीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कदम नहीं उठाए गए, तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता।

OCM अमलाई खदान हादसा: 3 माह बाद डम्पर ट्रक सहित चालक का शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

थाना अमलाई क्षेत्र अंतर्गत 11 अक्टूबर 2025 को OCM खदान में डम्पर ट्रक चालक सहित डूब जाने की घटना में करीब तीन माह बाद बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से चले आ रहे रेस्क्यू प्रयासों के बाद आज डम्पर ट्रक के साथ चालक का शव बरामद कर लिया गया। घटना के दिन खदान में डम्पर ट्रक चालक सहित डूब गया था। रेस्क्यू के लिए तत्काल NDRF एवं SDERF अनूपपुर की संयुक्त टीम ने प्रयास किए थे, लेकिन ट्रक लगभग 100 मीटर से अधिक गहराई में होने के कारण सफलता नहीं मिल सकी थी। इसके बाद से खदान से लगातार पानी निकाला जा रहा था। <

आज सुबह लगभग 8:15 बजे SECL प्रबंधन द्वारा सूचना दी गई कि खदान में डूबा डम्पर ट्रक दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही जिला सेनानी के नेतृत्व में SDERF अनूपपुर एवं शहडोल की 08 सदस्यीय संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए OCM अमलाई खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद डम्पर ट्रक सहित वाहन चालक की डेड बॉडी को सफलतापूर्वक बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को समाप्त घोषित किया गया।

मृतक का विवरण- मृतक की पहचान अनिल कुशवाहा (पिता शिवदत्त प्रसाद), उम्र 40 वर्ष, निवासी मउगंज, जिला मउगंज रीवा के रूप में हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अधिकारी एवं जवानों की भूमिका सराहनीय इस चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान में SDERF अनूपपुर एवं शहडोल की टीमों ने साहस, धैर्य और पेशेवर दक्षता का परिचय दिया। खदान की गहराई और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद संयुक्त टीम ने सफलता हासिल कर एक लंबे समय से प्रतीक्षित राहत दिलाई।

ट्रक बैक करने के दौरान क्लीनर आया पहिए के नीचे, हुई मौत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कदौरा(जालौन): थाना क्षेत्र के भेड़ी खदान संख्या तीन में उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक ट्रक बैक हो रहा था और क्लीनर ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक का पिछला पहिया उसके शरीर के ऊपर से निकल गया जिससे क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूद साथी उसे घायल अवस्था में सीएचसी लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी निवासी कमल पुत्र सुखलाल प्रजापति उम्र 19 वर्ष ट्रक पर सवार होकर भेड़ी खदान में मौरम भरने के लिए गया हुआ था। खदान में ट्रक बैक हो रहा था उसी समय कमल ट्रक की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित

कर दिया। जैसे ही घटना की सूचना परिजनों को मिली, परिवार में मातम छा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी प्रभात कुमार सिंह का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ट्रक की स्थिति, चालक की भूमिका और दुर्घटना के समय की परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है। मृतक क्लीनर की मां भूरी देवी के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है, अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

शराबी पति से तंग आकर 2 बच्चों की मां ने प्रेमी संग रचाई शादी

माधौगढ़ (जालौन): कोतवाली क्षेत्र से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार 2 बच्चों की मां ने कथित रूप से अपने शराबी पति की मारपीट से तंग आकर प्रेमी के साथ नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। महिला अपने प्रेमी के साथ माधौगढ़ से चली गई और दोनों ने ईश्वर को साक्षी मानकर एक-दूसरे के साथ जीवनभर साथ निभाने की कसमें खाकर विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों की ओर से एक के बाद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किए गए हैं जो देखते ही देखते वायरल हो गए हैं। वायरल वीडियो में दंपती अपने फैसले को स्वेच्छा से लिया गया कदम बता रहे हैं। फिलहाल मामला सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है। पुलिस स्तर पर किसी प्रकार की आधिकारिक शिकायत या कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर तरह-तरह की चर्चाएं जारी हैं।

विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण

● फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का आलेख्य प्रकाशन, राजनीतिक दलों के साथ समीक्षा बैठक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उरई (जालौन): भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने की। बैठक में अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर 6 जनवरी 2026 को विधानसभा क्षेत्र 219-माधौगढ़, 220-कालपी एवं 221-उरई (अजा) के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों, मतदेय स्थलों, ईआरओ/एईआरओ कार्यालयों तथा जिला निर्वाचन कार्यालय पर फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का आलेख्य प्रकाशन विधिवत रूप से किए जाने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी दोनों स्वरूपों में उपलब्ध कराई गई ताकि वे सूची का अवलोकन कर निर्धारित समयसीमा में आपत्ति, दावा अथवा संशोधन प्रस्तुत कर सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण एवं अद्यतन प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे मतदाता

सूची में अपना नाम, विवरण एवं फोटो अवश्य जांच लें जिससे कोई भी पात्र मतदाता आगामी चुनावों में अपने मताधिकार से वंचित न रहे। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सहित भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, अपना दल (सोनेलाल), सीपीआई (एम) के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

लोगों को विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपये ऐंठने वाले कबूतरबाज की शिकायत डीआईजी से की

हमीरपुर :- मौदहा कस्बा के बड़ चौराहा कम्हरिया रोड निवासी शमीमुद्दीन पुत्र फैयाजुद्दीन ने डीआईजी को भेजे गए शिकायती पत्र में कहा है कि कस्बा के मोहल्ला उपरौस निवासी सैफुल हयात पुत्र हयात ने क्षेत्रीय शिक्षित बेरोजगार नव युवकों को विदेश में नौकरी का झांसा देकर प्रत्येक से 4-5 लाख रुपया ठग कर उक्त पैसों से अरबों रुपये की सम्पत्ति जैसे प्लाट, खेत, मकान व अन्य कस्बों व शहरों में मॉल व चत्पल इत्यादि की कम्पनी बना ली है। उसने पीड़ित का भी 4,50,000/-रु0 (साढ़े चार लाख रुपये) लेकर धोखा धड़ी का शिकार बनाया है। स्थानीय पुलिस उक्त सैफुल हयात से व्यक्तिगत लाभ अर्जित कर संरक्षण प्रदान कर रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत दि0-21.12.2025 से अब तक विवेचक द्वारा उसके संचालित कार्यालय व प्रशिक्षण केन्द्र को बंद नहीं कराया है और न ही गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई है। जब कि आरोपी आये दिन प्रार्थी/आवेदक को मुकदमा वापस लेने एवं हत्या की धमकी दे रहा है। यदि समय रहते आरोपी की गिरफ्तारी नही की गई तो आवेदक की हत्या हो सकती है इसके लिए स्थानीय शासन व प्रशासन जिम्मेदार होगा।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका, युवाओं से की आगे आने कि अपील

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उरई (जालौन) भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत जनपद में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में दयानंद वैदिक कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, संशोधन एवं अद्यतन के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन नागरिकों की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है या उससे पहले हो चुकी थी, वे मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील करते

हुए कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे सशक्त कड़ी है। नए मतदाता आगे आकर पंजीकरण कराएं और अन्य पात्र नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही, उन्होंने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित, कॉलेज के प्राचार्य राजेश चंद्र पाण्डेय समेत शिक्षकगण, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

माघ मेले के लिए हमीरपुर से हर घंटे मिलेगी बस

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर :- संगम नगरी प्रयागराज में शनिवार से शुरू हुए माघ मेले के लिए बसें लगा दी गई है। बस के जरिए श्रद्धालु सुगम यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। माघ मेला शुरू होते ही हमीरपुर डिपो से प्रयागराज के लिए हर घंटे बसे रवाना की जा रही है। इसके लिए डिपो के बेड़े में शामिल 81 में से 55 बसो को विशेष रूप से मेला के लिए आरक्षित किया गया है। प्रयागराज में तीन जनवरी से शुरू हुए माघ मेला और कल्पवास के लिए श्रद्धालु रवाना हो रहे हैं। इस मौके पर कई जिलों से श्रद्धालु कल्पवास व स्नान के लिए प्रयागराज जाते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने भी जोरदार तैयारी की है। डिपो वर्कशॉप में तैनात कर्मचारी बसो की तकनीकी जांच और मरम्मत के बाद उसे ऑनरोड कर रहे हैं। इससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बताया गया की जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी मेला मार्ग पर भेजी जाएगी। हालांकि अभी भीड़ कम है। प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे श्रद्धालु विजय शंकर त्रिपाठी, चिंताहरण व रामरती ने बताया कि बसे आसानी से मिल गई। 25 बसे हमीरपुर वाया कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। वहीं 25 बसे हमीरपुर वाया बांदा होते हुए प्रयागराज भेजी जा रही है। इनमें 15 बसे हमीरपुर वाया प्रयागराज होते हुए लेप्रोसी बस अड्डा पहुंच रही है। प्रभारी एआरएम विनोद कुमार ने बताया कि दो जनवरी को आठ बसे भेजी गई थी। तीन बसे और लगाई गई है। हालांकि हर घंटे बसें रवाना की जा रही हैं।

पुलिस ने दबोचे आधा दर्जन जुआरी, 50 हजार से अधिक नगदी बरामद

कोंच(जालौन): कोतवाली पुलिस ने जुए के एक फड़ पर छापा मारकर आधा दर्जन जुआरियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जुआरियों के पास से 50 हजार रुपए से अधिक की नगदी भी बरामद की है। एसपी डॉ दुर्गेश कुमार के निर्देशन और सीओ परमेश्वर प्रसाद के पर्यवेक्षण में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार की दोपहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अटा में चकरोड के नजदीक स्थित एक खंडहर में हार जीत की बाजी लगा रहे रविकांत कोंच, उत्तम सिंह सिकंदरपुर, मानसिंह अटा, रामपाल अटा, ताराचंद भदेवरा, मानवेंद्र लोहागढ़ को पकड़ लिया। पुलिस ने मालफड़ से 52 हजार 590 रूपये बरामद किए हैं। पुलिस ने उपरोक्त सभी जुआरियों के विरुद्ध जुआ अधिनियम एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

संदिग्ध हालात में 12वीं के छात्र की मौत, 4 लोगों पर हत्या का आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उरई(जालौन): कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत चौरसी गांव में मंगलवार को 12वीं कक्षा के एक छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने बताया कि मृतक देवेंद्र जो 12वीं का छात्र था, का शव गांव में संदिग्ध हालात में मिला है। मौके पर पुलिस एवं फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं मृतक के पिता करन सिंह ने चार लोगों पर बेटे की हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि देवेंद्र को पहले शराब पिलाई गई इसके बाद उसकी हत्या कर शव को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या

का रूप देने की कोशिश की गई। परिजनों एवं ग्रामीणों के अनुसार, घटना के पीछे अवैध संबंधों का मामला सामने आ रहा है। मृतक के भाई रघुराज प्रताप सिंह ने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश है। परिजनों ने पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

रात्रि में डीएम ने अलाव, शेल्टर होम और मंडी की जमीनी हकीकत परखी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कोंच(जालौन): शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने सोमवार की रात्रि में कोंच नगर क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने एडीएम न्यायिक, एसडीएम और एसडीएम न्यायिक के साथ नगर में जलाए जा रहे अलावों, शेल्टर होम, मंडी परिसर, धर्मकांटा और गौशाला की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड से बचाव की सभी व्यवस्थाएं हर हाल में दुरुस्त रखें और किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि जहां-जहां स्थाई स्थान चिह्नित हैं, वहां अलावों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही पिछले वर्ष जिन मोहल्लों में अलाव जलाए जाते थे वहां भी अनिवार्य रूप से अलाव जलाए जाएं। इसके अलावा नए विकसित मोहल्लों और जरूरतमंद क्षेत्रों को भी अलाव व्यवस्था में शामिल करने के उन्होंने निर्देश दिए। अलावों को देखने के बाद डीएम ने गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौवंशों को गुड़ खिलाया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शेल्टर होम निरीक्षण के दौरान करीब 9 व्यक्ति ठंड से बचाव के लिए ठहरे हुए मिले। डीएम ने संतोष जताया कि शेल्टर होम में ठहरने वालों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। गल्ला मंडी में डीएम ने मटर की आवक, खरीद दर और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण में पाया गया कि प्रवेश पर्ची मंडी गेट पर न काटकर अंदर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पास काटी जा रही थी। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने निर्देश दिए कि प्रवेश पर्ची अनिवार्य रूप से मंडी गेट पर ही काटी जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और अव्यवस्था न हो। साथ ही ट्रैफिक जाम न लग सके इसका भी विशेष ध्यान रखने को उन्होंने जिम्मेवारों से कहा। निरीक्षण के दौरान यहां पर स्थापित धर्मकांटा खराब मिला। इस पर डीएम ने तत्काल धर्मकांटा दुरुस्त कराने और आवश्यकता पड़ने पर नया धर्मकांटा लगवाने के निर्देश दिए। मटर की फली बेचने आए हुए किसानों से संवाद करते हुए डीएम ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और भुगतान में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंडी व्यापारियों से बातचीत में डीएम ने स्पष्ट किया कि किसानों का भुगतान समय से किया जाए ताकि उन्हें

आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान मटर की गुणवत्ता का भी डीएम ने अवलोकन किया। डीएम ने कहा कि उत्पादकता में बहुत अधिक अंतर नहीं दिखा, हालांकि इस बार मटर की फसल कुछ कमजोर नजर आ रही है। उधर, नगर भ्रमण के दौरान डीएम ने रात में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों और गंदगी वाले क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़ा निकासी और उठान की व्यवस्था में सुधार किया जाए। निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन और मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहकर जनता को राहत पहुंचाएं। इस दौरान एडीएम न्यायिक सहित एसडीएम ज्योति सिंह, एसडीएम न्यायिक वीरेंद्र प्रसाद, ईओ नगर पालिका मोनिका उमराव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

माघ गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं ने गढ़ी स्थित गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना

कोंच(जालौन): प्राचीन श्री गणेश मंदिर गढ़ी पर मंगलवार को श्री माघ गणेश चतुर्थी व्रत मेले का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान लंबोदर का दर्शन लाभ प्राप्त किया। श्री गणेश सेवा समिति प्राचीन मंदिर गढ़ी कोंच के तत्वाधान में माघ गणेश चतुर्थी व्रत मेले का आयोजन किया गया, समिति के पदाधिकारियों ने व्यवस्थाएं देखीं। माघ चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। यह मेला पिछले कई दशकों से आयोजित होता आ रहा है। ज्योतिर्विद पं. संजय रावत ने श्री आघ गणेश चतुर्थी व्रत की महिमा बताते हुए कहा कि इस व्रत को करने से सभी संकटों का निवारण होता है। यह माघ कृष्ण चतुर्थी, संकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। इस चतुर्थी को 'श्री गणेशोत्पत्ति' आघ बड़े गणेश माघी कृष्ण चतुर्थी', 'तिलचौथ', 'वक्रतुंडी चतुर्थी' आदि नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश भगवान तथा संकट माता की पूजा का विधान है। संकष्ट का अर्थ है 'कष्ट या विपत्ति', 'कष्ट' का अर्थ है 'क्लेश', सम् उसके आधिक्य का द्योतक है। आज किसी भी प्रकार के संकट, कष्ट का निवारण संभव है। आज के दिन व्रत रखा जाता है।

जाम से मुक्ति की दिशा में सख्त पहल, व्यापारियों के सहयोग से चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान- जिलाधिकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

उरई (जालौन): शहर को जाम की समस्या से स्थायी राहत दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार की उपस्थिति में कोतवाली उरई में शहर के प्रमुख व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने एवं अतिक्रमण हटाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क मार्गों पर ठेले, खोमचे एवं अस्थायी अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा है। इसी को देखते हुए शहर में वेंडिंग जोन निर्धारित किए गए हैं ताकि छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से रोजगार मिल सके और यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि वे स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटा लें। उन्होंने विशेष रूप से फुटपाथों पर किए गए अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पैदल चलने

वाले नागरिकों को गंभीर असुविधा होती है। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि 8 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पुलिस, राजस्व, लोक निर्माण विभाग एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी। बैठक में व्यापारियों ने प्रशासन की पहल का समर्थन करते हुए शहर को जाम-मुक्त बनाने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा, सीओ सिटी अर्चना सिंह, व्यापारी नेता दिलीप सेठ, संतोष गुप्ता, अरुण त्रिपाठी सहित अन्य व्यापारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

समाजसेवी बिश्वजीत कैरी भाजपा पार्टी के उम्मीदवार और प्रत्याशी के रूप में राजनीतिक बायोडाटा औपचारिक रूप से जिला अध्यक्ष कल्याण गोस्वामी के हाथों सौंपा

● राजनीतिक जीवन में सफलता के लिए गुरु महाराज और धर्मगुरु श्री श्री गौतम मिश्रा जी का आशीर्वाद लिया।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: गत 5 जनवरी (सोमवार) को राजनीतिक जीवन में सफलता के लिए गुरु महाराज और धर्मगुरु श्री श्री गौतम मिश्रा जी का आशीर्वाद लिया और आगामी असम विधानसभा चुनाव 26 में 121 नंबर हाइलाकांडी विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और प्रत्याशी के रूप में अपना राजनीतिक बायोडाटा औपचारिक रूप से जिला अध्यक्ष श्री कल्याण गोस्वामी महाशय के हाथों सौंपा। इस सौंपने के आयोजन में उनके साथ उपस्थित होकर आशीर्वाद और उत्साह प्रदान किया और विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय वरिष्ठ नागरिक आनंद राय, सुमन पांडे, श्री अमित कुमार डे (सानी), हाइलाकांडी टाउन मंडल अध्यक्ष, प्रीतीश कुमार दास, वरिष्ठ वकील, हाइलाकांडी मिस्तुनाथ (मिस्टू), मैपाक सिंह, विशाल शील, प्रभु नारायण करपात्री साधु बाबा जी, विजय ग्वाला, मुन्ना बराई, रामराज रविदास, शिवा कुर्मी, सुमन दास और सभी शुभचिंतक और उत्साही सहयोगियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और अभिनंदन व्यक्त किया।

थाना परिसर में साइबर हेल्प डेस्क का हुआ उद्घाटन

कदौरा(जालौन): मंगलवार को पुलिस अधीक्षक डॉ दुर्गेश कुमार ने कस्बे के थाना परिसर में नव निर्मित साइबर हेल्प डेक्स का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर थाना क्षेत्र के चौकीदारों को कंबल वितरित कर उन्हें अपने-अपने गांवों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश एसपी ने दिए। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए यह साइबर हेल्प डेस्क आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। अब साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों के लिए लोगों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिससे संबंधित मामलों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही पांच महिला आरक्षियों की कदौरा थाना में तैनाती की जाएगी। उन्होंने चौकीदारों से कहा कि गांवों की सुरक्षा व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसका निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करें। इस दौरान उन्होंने वृद्ध चौकीदारों से अपने बच्चों के नाम प्रस्ताव भेजने को कहा ताकि भविष्य में उनके बच्चों को जिम्मेवारी सौंपी जा सके। एसपी ने प्रभारी निरीक्षक प्रभात सिंह को निर्देश दिये कि महिला अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाए और महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा आपराधिक घटना को सख्ती से रोका जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया गया कि साइबर हेल्प डेस्क पर पांच सदस्यीय टीम कार्य करेगी जो साइबर अपराधों से संबंधित मामलों का पंजीकरण कर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करेगी। कार्यक्रम में एएसपी प्रदीप कुमार वर्मा, सीओ एके सिंह, अजय सिंह, प्रभात सिंह, सुजीत मिश्रा, रमेश सिंह चौहान, अंकित चौरसिया, अशोक आदि उपस्थित रहे।